बुधवार , 18 नवंबर 2026, ठाणे, मुंबई

दैनिक सिटी न्यूज मुंबई

सच का जोश

वर्ष - 15 • अंक - 82

CITY NEWS MUMBAI

महाराष्ट्र कैबिनेट के 4 बड़े फैसले

पालघर को नया जिला न्यायालय, नक्सलियों के हथियारों की सूचना पर नकद इनाम

महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में चार बड़े फैसले लिए गए। पालघर में जिला एवं सत्र न्यायालय बनेगा, टेक्सटाइल नीति में बदलाव हुआ और नक्सल हथियारों की सूचना पर नकद इनाम मिलेगा। नक्सलियों के कब्जे में मौजूद लूटे गए हथियारों की जानकारी देने वालों को नकद इनाम मिलेगा। महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 में संशोधन किया जाएगा। उच्च शिक्षा में बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप होंगे। पालघर में प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायालय और मुख्य दंडाधिकारी न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की मंगलवार को हुई बैठक में गृह, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, वस्त्रोद्योग और विधि एवं न्याय विभाग से जुड़े चार महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकार ने नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों से पहले लूटे गए हथियारों की जानकारी देने वालों के लिए नकद इनाम योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा राज्य में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2016 में संशोधन किया जाएगा। वहीं, पालघर जिले को न्यायिक सुविधाओं की बड़ी सौगात देते हुए वहां प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायालय तथा मुख्य दंडाधिकारी न्यायालय स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। नक्सलियों के हथियारों की जानकारी देने पर इनाम कैबिनेट ने नक्सलियों द्वारा सुरक्षा



बलों से पहले लूटे गए हथियारों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले लोगों के लिए नकद पुरस्कार योजना को मंजूरी दी है। इस फैसले का उद्देश्य नक्सलियों के कब्जे में मौजूद हथियारों का पता लगाने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में मदद हासिल करना है। इससे सुरक्षा एजेंसियों को नक्सल गतिविधियों पर नियंत्रण के प्रयासों में सहयोग मिलने की उम्मीद है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप बदलेगा विश्वविद्यालय कानून महाराष्ट्र राज्य में उच्च और तकनीकी शिक्षा का स्तर बेहतर बनाने के लिए महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 में संशोधन करने का फैसला लिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा व्यवस्था में होने वाले बदलावों को ध्यान में रखते हुए यह संशोधन किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली और शैक्षणिक व्यवस्था को नई जरूरतों के अनुरूप तैयार करना है। इससे राज्य के उच्च शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का रास्ता खुल सकता है। पालघर के टेक्सटाइल उद्योग को राहत मंत्रिमंडल ने एकीकृत एवं सतत वस्त्रोद्योग नीति में संशोधन को भी मंजूरी दी है। इसके तहत पालघर जिले को अब जोन-1 में शामिल किया जाएगा। साथ ही जोन-4 की वर्गवारी समाप्त करने और उद्योगों के विस्तार से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया जाएगा। इस फैसले से पालघर में वस्त्रोद्योग से जुड़े निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। पालघर में बनेगा प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायालय पालघर जिले के लिए कैबिनेट का एक महत्वपूर्ण फैसला न्यायिक व्यवस्था से जुड़ा है। अब पालघर में प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायालय के साथ मुख्य दंडाधिकारी न्यायालय की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा सरकारी वकीलों के कार्यालय और उनसे संबंधित आवश्यक पदों के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है।

रात के अंधेरे में दो बच्चियों को बस से बीच सड़क पर उतारने वाले भंडारा डिपो के चालक और कंडक्टर निलंबित

महाराष्ट्र में एसटी बस से रात के अंधेरे में दो नाबालिग बच्चियों को रोहा में उतारने के मामले में चालक और कंडक्टर निलंबित कर दिए गए हैं। रात में दो बच्चियों को बीच रास्ते उतारने पर ST के चालक-कंडक्टर निलंबित। 14 नवंबर को रोहा में हुई थी घटना, भंडारा डिपो के कर्मचारी दोषी पाए गए। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक की चेतावनी, लापरवाही पर होगी बर्खास्तगी। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन महामंडल (एसटी) की बस में सफर कर रही दो नाबालिग बच्चियों को रात के अंधेरे में बीच रास्ते उतारने के



मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। परिवहन मंत्री एवं महामंडल के अध्यक्ष प्रताप सरनाईक के निर्देश पर हुई प्राथमिक जांच में लापरवाही सामने आने के बाद चालक और कंडक्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मंत्री ने चेतावनी दी है कि भविष्य में यात्रियों, विशेषकर महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को सीधे सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है। 14 नवंबर की रात रोहा में हुई घटना यह घटना 14 नवंबर की रात की है। भंडारा डिपो की एसटी बस में यात्रा कर रही दो मासूम बच्चियों को रोहा में रात के अंधेरे के दौरान बस से उतार दिया गया था।

इस घटना की जानकारी सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद एसटी प्रशासन की कार्यप्रणाली और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे।

मुंबई मेट्रो-5 को मिली बड़ी कामयाबी, कशेली डिपो पहुंची पहली ट्रेन; ठाणे-कल्याण के यात्रियों को मिलेगी राहत



मुंबई मेट्रो लाइन-5 के कशेली डिपो में पहली ट्रेन पहुंच गई है। ठाणे-भिवंडी-कल्याण कॉरिडोर के परीक्षण और नए साल से यात्री सेवा शुरू होने की राह आसान हो गई है। मुंबई मेट्रो लाइन-5 की पहली ट्रेन कशेली डिपो पहुंच गई है। यह कॉरिडोर ठाणे, भिवंडी और कल्याण को जोड़ेगा। करीब 27 हेक्टेयर में फैले डिपो में 30 ट्रेन सेट रखने की क्षमता होगी। नए साल से मेट्रो सेवा शुरू होने की संभावना जताई गई है।

बालासाहेब ठाकरे की सच्ची विरासत को आगे बढ़ा रही शिवसेना, एकनाथ शिंदे बोले- 80-20 के फॉर्मूले पर चल रही सरकार



डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बालासाहेब ठाकरे की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा महायुति सरकार 80% समाजनीति, 20% राजनीति के मूलमंत्र पर काम कर रही। एकनाथ शिंदे ने बालासाहेब ठाकरे की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि बालासाहेब के 80% समाजनीति और 20% राजनीति के मूलमंत्र पर काम कर रही है महायुति सरकार एकनाथ शिंदे ने कहा कि किसानों की आर्थिक सहायता के लिए सभी दल एकजुट हों महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री ...शेष 7 पर

25 साल में 1 लाख मजदूरों में सिर्फ 17 हजार को मिले घर, मुंबई में ही आशियाने की मांग पर आंदोलन

मुंबई में मिल मजदूरों को घर देने का 25 साल पुराना वादा अब भी अधूरा है। एक लाख से अधिक मजदूरों में सिर्फ 17 हजार को घर मिले हैं। 25 साल में एक लाख से ज्यादा मिल मजदूरों में से सिर्फ 17 हजार को मिले घर। मुंबई में ही आवास की मांग को लेकर 16 मजदूर संगठनों का लालबाग में आंदोलन। वांगणी में घर लेने से इनकार, मुंबई में 1.25 लाख घर बनाने की मांग। मुंबई के औद्योगिक विकास में अपना पसीना बहाने वाले मिल मजदूरों के अपने ही शहर में खुद का घर पाने का सपना ढाई दशक बीतने



के बाद भी अधूरा है। राज्य सरकार द्वारा साल 2001 में घर देने का निर्णय लिए जाने के बावजूद 25 साल में एक लाख से ज्यादा मिल मजदूरों में से सिर्फ 17 हजार को ही आवास मिल पाए हैं, जबकि शेष मजदूर और उनके परिवार आज भी छत के इंतजार में हैं। ऐसे में अब जमीन की कमी का हवाला देकर मजदूरों को मुंबई से बाहर बसाने की सरकारी नीति और पिछले 15 वर्षों से चल रही टालमटोल के खिलाफ भारी आक्रोश भड़क उठा है। इसके विरोध में और मुंबई में ही आशियाना मुहैया कराए जाने की मांग को लेकर सोमवार को लालबाग के भारतमाता सिनेमाघर के पास 16 मजदूर संगठनों ने एकजुट होकर आंदोलन किया। आंदोलन में शामिल मिल मजदूरों की नारेबाजी से गूंजा लालबाग परिसर गिरणी कामगार संयुक्त लढा समिति के बैनर तले सोमवार को आयोजित धरना आंदोलन में शामिल मिल मजदूरों की नारेबाजी से लालबाग परिसर गूंज उठा। समिति ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार पिछले ...शेष 7 पर

भारत समिट विवाद: सुप्रीम कोर्ट में याचिका, विदेशी नेता के वोट चोर, गद्दी छोड़ नारे की SIT जांच की मांग

13-14 नवंबर को हैदराबाद में भारत समिट 2026 कार्यक्रम के दौरान विदेशी नेता जियाकोमो फिलिबेक की ओर से राहुल गांधी के समर्थन में दिए गए विवादित बयान पर SC में दायर हुई याचिका। भारत समिट के दौरान विदेशी नेता के विवादित बयान पर सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हुई याचिका इटली के नेता जियाकोमो फिलिबेक ने राहुल गांधी और कांग्रेस के समर्थन में दिया था विवादित बयान याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से स्वतंत्र SIT गठित कर पूरे प्रकरण की जांच कराने का अनुरोध हैदराबाद में आयोजित भारत समिट 2026 के दौरान दिए गए एक कथित राजनीतिक नारे को लेकर विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। मामले में एक याचिका दाखिल कर पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने इस उद्देश्य से विशेष जांच दल (SIT) के गठन की अपील की है। दरअसल, तेलंगाना सरकार ने 13 और 14 नवंबर को हैदराबाद में भारत समिट 2026 का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम के दौरान इटली के नेता और पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक की ओर से राहुल गांधी के समर्थन में कथित तौर पर 'वोट चोर, गद्दी छोड़' का नारा लगाए जाने की बात सामने आई।



इस घटना के बाद समिट को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए। इस मामले में वकील जाहिद अली ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि समिट में शामिल विदेशी प्रतिनिधियों ने भारत के आंतरिक राजनीतिक मामलों में दखल दिया। साथ ही, उनके वीजा नियमों के संभावित उल्लंघन की भी जांच कराने की मांग उठाई गई है। SIT गठित करने की मांग याचिका में सुप्रीम कोर्ट से स्वतंत्र SIT गठित कर पूरे प्रकरण की जांच कराने का अनुरोध किया गया है। इसके अलावा समिट के आयोजन और विदेशी प्रतिनिधियों को दी गई सरकारी अनुमति की भी पड़ताल करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने तेलंगाना सरकार से सार्वजनिक माफी मांगने, विवाद से जुड़े वीडियो हटाने तथा सभी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के निर्देश देने की अपील भी की है। भाजपा ने भी दर्ज कराई शिकायत वहीं, इस मुद्दे पर तेलंगाना भाजपा ने भी 16 नवंबर को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) में शिकायत दर्ज कराई थी। पार्टी ने जियाकोमो फिलिबेक और समिट के आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल, भारत समिट में कथित नारेबाजी का मामला राजनीतिक विवाद से निकलकर कानूनी लड़ाई तक पहुंच चुका है। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर टिकी हैं। याचिका पर अदालत का अंतिम फैसला आना बाकी है। जियाकोमो फिलिबेक ने क्या कहा था? जियाकोमो फिलिबेक ने अपने संबोधन में कहा कि मतदाता सूची को साफ-सुथरा और पारदर्शी बनाने के लिए राहुल गांधी का अभियान लोकतंत्र की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

रिंकू सिंह ने प्रिया सरोज को प्यार के जाल में कैसे फंसाया? कैसे शुरू हुई दोनों की लव स्टोरी



रिंकू सिंह और सांसद प्रिया सरोज की शादी चार दिसंबर को होगी। उनकी प्रेम कहानी कोविड काल में आईपीएल के दौरान शुरू हुई थी। जानिए पहली बातचीत से शादी तक कैसे। रिंकू सिंह ने बताया कि 2022 में आईपीएल के दौरान प्रिया सरोज की तस्वीर देखकर उन्हें प्यार हुआ। प्रिया के फोटो लाइक करने के बाद रिंकू ने उन्हें मैसेज किया, फिर दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। सांसद बनने के बाद प्रिया की व्यस्तता बढ़ी, अब दोनों की ज्यादातर बातचीत रात में होती है। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। दोनों की शादी 4 दिसंबर को होनी है। दोनों की सगाई पिछले साल यानी 8 जून 2025 को हुई थी। शादी से पहले रिंकू सिंह ने अपनी लव स्टोरी को लेकर कई दिलचस्प खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि कैसे एक फैन पेज पर प्रिया की तस्वीर देखकर उन्हें पहली नजर में उनसे प्यार हो गया था। इसके बाद उन्होंने हिम्मत जुटाकर प्रिया को मैसेज किया और धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। रिंकू सिंह ने न्यूज 24 से बातचीत में बताया कि उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत साल 2022 में कोविड महामारी के दौरान हुई थी। उस समय आईपीएल के मुकाबले मुंबई में खेले जा रहे थे। इसी दौरान उनके एक फैन पेज पर प्रिया सरोज की तस्वीर पोस्ट की गई थी। बताया जाता है कि यह तस्वीर उनके गांव में मतदान से जुड़ी थी। रिंकू की नजर जब इस फोटो पर पड़ी तो उन्हें प्रिया पसंद आ गईं। उन्होंने महसूस किया कि प्रिया उनके लिए एक परफेक्ट जीवनसाथी हो सकती हैं। रिंकू सिंह को पहले मैसेज करने में हो रही थी झिझक रिंकू ने बताया कि प्रिया की तस्वीर देखने के बाद वह उनसे संपर्क करना चाहते थे, लेकिन शुरुआत में मैसेज भेजने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। हालांकि, जब उन्होंने देखा कि प्रिया उनकी तस्वीरों को लाइक कर रही हैं तो उन्हें बातचीत शुरू करने का मौका मिल गया। इसके बाद रिंकू ने उन्हें इंस्टाग्राम पर मैसेज किया और दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। कुछ ही हफ्तों में यह बातचीत रोजाना होने लगी। रिंकू ने बताया कि क्रिकेट मैचों से पहले भी दोनों बात किया करते थे। इसी दौरान उन्हें महसूस होने लगा कि वह प्रिया से प्यार करने लगे हैं। इस तरह सोशल मीडिया पर शुरू हुई दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई। प्रिया सरोज के सांसद बनने के बाद कम हो गई दोनों की बातचीत रिंकू सिंह ने बताया कि जब प्रिया सरोज साल 2024 में सांसद बनीं तो उन्हें काफी खुशी हुई। वह उनके सामाजिक कार्यों और लोगों की मदद करने के जज्बे की तारीफ करते हैं। हालांकि, सांसद बनने के बाद दोनों के बीच बातचीत पहले के मुकाबले कम हो गई है। रिंकू के मुताबिक, प्रिया अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों से मिलती हैं, गांव जाती हैं और संसद की जिम्मेदारियां निभाती हैं।

डीजल निर्यात शुल्क में 2.5 रुपये की बढ़ोतरी, ATF भी हुआ महंगा, नई दरें इस तारीख से होंगी लागू



डीजल और ATF के निर्यात पर सरकार ने विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है। पेट्रोल के निर्यात पर किसी तरह का शुल्क नहीं लगाया गया है।16 नवंबर से नई दरें लागू हो गई हैं। डीजल के निर्यात शुल्क में 2.50 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी ATF के निर्यात पर भी बढ़ा शुल्क, नई दरें 16 नवंबर से लागू अक्टूबर के बाद दूसरी बार बढ़ा विंडफॉल टैक्स, पेट्रोल निर्यात शुल्क शून्य केंद्र सरकार ने डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स (अतिरिक्त लाभ कर) में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि, पेट्रोल के निर्यात पर किसी तरह का शुल्क नहीं लगाया गया है। सरकार के इस फैसले से डीजल और ATF का निर्यात करने वाली कंपनियों पर शुल्क का बोझ बढ़ जाएगा। वित्त मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी दो अलग-अलग अधिसूचनाओं के मुताबिक, डीजल पर निर्यात शुल्क 11.50 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।

गोल्डी ढिल्लों ने दी धमकी, आखिर अमिताभ बच्चन का 1984 के सिख विरोधी हिंसा से क्या है कनेक्शन?



गोल्डी ढिल्लों की अमिताभ और अभिषेक बच्चन को धमकी के बाद 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़ा विवाद फिर चर्चा में है। जानिए अमिताभ सिख विरोधी हिंसा से कनेक्शन। गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों ने सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन को धमकी दी है। इस धमकी के बाद 1984 के सिख विरोधी दंगों का विवाद फिर चर्चा में आया। अमिताभ बच्चन ने उन पर लगे सभी पुराने आरोपों को हमेशा बेबुनियाद बताया है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन को गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों की ओर से कथित धमकी दिए जाने के बाद करीब 42 साल पुराना विवाद फिर चर्चा में आ गया है। गोल्डी ढिल्लों ने सोशल मीडिया पर धमकी भरे संदेश में 1984 के सिख विरोधी दंगों का जिक्र किया और आरोप लगाया कि उस हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को कभी माफ नहीं किया जाएगा। इसी संदर्भ में उसने अमिताभ और अभिषेक बच्चन का नाम लिया।

बालासाहेब ठाकरे की पुण्यतिथि पर नेताओं ने दी श्रद्धांजलि, शिवराज सिंह चौहान से योगी आदित्यनाथ तक ने किया याद



बालासाहेब ठाकरे की पुण्यतिथि पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल और सीएम योगी समेत कई दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि। बालासाहेब ठाकरे की पुण्यतिथि पर केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने दी श्रद्धांजलि। शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल और योगी आदित्यनाथ ने किया नमन। धामी, नायब सैनी और भजनलाल शर्मा ने भी एक्स पर साझा किया संदेश। नई दिल्ली, 17 नवंबर (आईएएनएस)। शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे की पुण्यतिथि पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि दी। शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के विकास में योगदान को किया याद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पोस्ट में कहा, "राष्ट्रवाद के ओजस्वी स्वर, अद्वितीय वक्ता, शिवसेना के संस्थापक, जननेता बालासाहेब ठाकरे की पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं! महाराष्ट्र के विकास में अहम योगदान और अपने प्रखर विचारों के लिए सदैव हमारे हृदय में अमर रहेंगे।" मनोहर लाल ने साहस और स्पष्टवादिता को सराहा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने एक्स पर पोस्ट किया, "प्रखर राष्ट्रवादी एवं जनप्रिय नेता, शिवसेना के संस्थापक आदरणीय बालासाहेब ठाकरे की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। उनका जीवन साहस, स्पष्टवादिता और सांस्कृतिक स्वाभिमान की अद्भुत मिसाल रहा। उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों और विचारधारा से समझौता नहीं किया। राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए उनका अडिग समर्पण सदैव हमें कर्तव्यपथ पर अग्रसर रहने की प्रेरणा देता रहेगा।" योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य ने किया नमन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने एक्स पर लिखा, "शिवसेना के संस्थापक आदरणीय बालासाहेब ठाकरे की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। बालासाहेब विचारों से दृढ़ एवं राष्ट्रीय मूल्यों के सच्चे समर्थक थे, उनका राष्ट्रवादी व्यक्तित्व हम सभी के लिए एक प्रेरणा है।" धामी और नायब सैनी ने भी दी श्रद्धांजलि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर लिखा, "प्रखर राष्ट्रवादी विचारधारा के संवाहक, ओजस्वी वक्ता एवं निर्भीक नेतृत्व के प्रतीक श्रद्धेय बालासाहेब ठाकरे की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। सांस्कृतिक अस्मिता, राष्ट्रीय स्वाभिमान और अपने सिद्धांतों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए उनका सार्वजनिक जीवन सदैव स्मरण किया जाएगा।"

कोलकाता में आज से सागर सुरक्षा 2026 का आगाज, तटीय सुरक्षा मजबूत करने के लिए जुटेंगे देशभर के वरिष्ठ अधिकारी

16-17 नवंबर 2026 तक कोलकाता में दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन सागर सुरक्षा 2026 का आयोजन हो रहा है। उद्देश्य देश में एक एकीकृत और मजबूत तटीय सुरक्षा ढांचा विकसित करना है। कोलकाता में दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन सागर सुरक्षा 2026 का आयोजन सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य देश में एक एकीकृत और मजबूत तटीय सुरक्षा ढांचा विकसित करना सम्मेलन में समुद्री सुरक्षा से जुड़ी मौजूदा चुनौतियों और भविष्य में सामने आने वाले संभावित खतरों पर होगी विस्तार से चर्चा भारत की तटीय और समुद्री सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से भारतीय तटरक्षक बल गृह मंत्रालय (MHA) के सीमा प्रबंधन विभाग के सहयोग से 16 से 17 नवंबर 2026 तक कोलकाता में दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन सागर सुरक्षा 2026 का आयोजन कर रहा है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य देश में एक एकीकृत और मजबूत तटीय सुरक्षा ढांचा विकसित करना है। सम्मेलन की थीम तटीय सुरक्षा के लिए व्यापक दृष्टिकोण, हितधारकों की भागीदारी और सामुदायिक जुड़ाव को मजबूत करना रखी गई है। कार्यक्रम का उद्घाटन पश्चिम बंगाल सरकार के



गृह एवं पर्वतीय मामलों के राज्य मंत्री बिशाल लामा करेंगे। देशभर की सुरक्षा एजेंसियों के प्रतिनिधि होंगे शामिल भारतीय तटरक्षक बल गृह मंत्रालय (MHA) के सीमा प्रबंधन विभाग के इस राष्ट्रीय सम्मेलन में तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ केंद्रीय मंत्रालयों, सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और समुद्री क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रमुख प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में समुद्री सुरक्षा से जुड़ी मौजूदा चुनौतियों और भविष्य में सामने आने वाले संभावित खतरों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। समुद्री सुरक्षा की चुनौतियों और खतरों पर होगा मंथन सागर सुरक्षा 2026 में समुद्री क्षेत्र की परिचालन संबंधी चुनौतियों, तटीय सुरक्षा की कमजोरियों और उभरते खतरों के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श होगा। इसके साथ ही सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने और किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए समन्वित प्रतिक्रिया तंत्र विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। तटीय सुरक्षा के लिए बनेगी साझा रणनीति सम्मेलन में विभिन्न एजेंसियां अपने अनुभव और परिचालन से जुड़ी सर्वोत्तम कार्यप्रणालियां साझा करेंगी। चर्चाओं के माध्यम से व्यावहारिक नीतिगत सुझाव तैयार करने, एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाने और सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। इस सम्मेलन का व्यापक लक्ष्य भारत की लंबी तटरेखा और समुद्री हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके जरिए एकीकृत राष्ट्रीय दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए देश की तटीय सुरक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी और मजबूत बनाने पर जोर दिया जाएगा।

भारतीय सेना में ब्रिगेडियर का पद खत्म? कर्नल से सीधे बनेंगे मेजर जनरल

क्या भारतीय सेना में ब्रिगेडियर का पद खत्म होने वाला है? जानिए कर्नल से सीधे मेजर जनरल बनने के प्रस्ताव से प्रमोशन, कमांड व्यवस्था और अधिकारियों के करियर पर क्या असर पड़ेगा। भारतीय सेना ब्रिगेडियर का पद समाप्त कर कर्नल से सीधे मेजर जनरल बनाने के प्रस्ताव पर कर रही है विचार। सेना अधिकारियों को मेजर जनरल के वेतन स्तर तक पहुंचने में 32-33 साल लगते हैं, जबकि सिविल सेवाओं में 16-18 साल। प्रस्ताव लागू होने पर ब्रिगेड की कमान मेजर जनरल संभाल सकते हैं, नौसेना और वायुसेना के रैंक ढांचे पर भी पड़ेगा असर। भारतीय सेना के रैंक ढांचे में आने वाले समय में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सेना ब्रिगेडियर का पद समाप्त करने और कर्नल से सीधे मेजर जनरल पद पर प्रमोशन देने की व्यवस्था पर विचार कर रही है। इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य अधिकारियों के प्रमोशन में होने वाली देरी को कम करना, करियर ग्रोथ



के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना और सिविल सेवाओं के साथ रैंक एवं वेतन संबंधी असमानता दूर करना है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक, इस प्रस्ताव को जल्द अंतिम रूप देकर आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के समक्ष रखा जा सकता है। 32-33 साल में मिलता है मेजर जनरल का पद मौजूदा व्यवस्था में सेना का रैंक ढांचा पिरामिड की तरह है। निचले और मध्य स्तर पर अधिकारियों की संख्या अधिक होने के कारण ऊंचे पदों तक पहुंचने के अवसर सीमित हो जाते हैं। आंकड़ों के मुताबिक, सेना के अधिकारियों को मेजर जनरल के वेतन स्तर तक पहुंचने में औसतन 32-33 साल लगते हैं। वहीं, आईएएस और आईपीएस जैसे सिविल सेवा अधिकारियों को समान स्तर तक पहुंचने में लगभग 16-18 साल लगते हैं। इसी अंतर को कम करने के लिए सेना ब्रिगेडियर का पद हटाने के विकल्प पर काम कर रही है। वर्ष 2018 में तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के कार्यकाल में भी इस विषय पर चर्चा हुई थी, लेकिन उस समय प्रस्ताव लागू नहीं हो पाया। मेजर जनरल संभालेंगे ब्रिगेड की कमान प्रस्ताव लागू होने पर ब्रिगेड की कमान ब्रिगेडियर के बजाय मेजर जनरल स्तर के अधिकारी संभाल सकते हैं। ये अधिकारी डिवीजन स्तर की जिम्मेदारियां भी निभाते रहेंगे। इससे कमांड व्यवस्था में बदलाव आएगा और नियमित अधिकारियों के लिए मेजर जनरल न्यूनतम रिटायरमेंट रैंक बनाने का विकल्प भी सामने है। नौसेना और वायुसेना पर भी पड़ेगा असर इस बदलाव का प्रभाव केवल थलसेना तक सीमित नहीं रहेगा। नौसेना में कमोडोर और वायुसेना में एयर कमोडोर के पद भी ब्रिगेडियर के समकक्ष हैं। इसलिए तीनों सेनाओं के रैंक ढांचे में तालमेल बैठाना होगा। लागू करने में होंगी कई चुनौतियां सेना में पहले ही एकीकृत बैटल ग्रुप (IBG) जैसी नई सैन्य संरचनाओं पर काम चल रहा है। प्रत्येक आईबीजी में लगभग 5,000 सैनिक होते हैं। ऐसे में प्रस्तावित बदलाव कमांड व्यवस्था को नया स्वरूप दे सकता है।

अयोध्या हमारी, अब मथुरा की बारी', केशव मौर्य की अखिलेश को खुली चुनौती; बोले- कार सेवा में साथ आइए



यूपी चुनाव 2027 से पहले केशव मौर्य ने मथुरा को लेकर बयान दिया और अखिलेश यादव को कार सेवा की चुनौती दी। उधर, बीजेपी ने चुनावी रणनीति बनाने के लिए मथुरा में बैठक की। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, 'अयोध्या हमारी है, अब मथुरा की बारी है।'

अखिलेश यादव को कार सेवा के लिए आगे आने की चुनौती दी। बीजेपी ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए मथुरा में दो दिवसीय योजना बैठक आयोजित की। पार्टी का फोकस ब्राह्मण, राजपूत, जाट और गुर्जर समुदायों की नाराजगी दूर करने के साथ बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने पर है। उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं।

पार्टी का लक्ष्य लगातार तीसरी बार प्रदेश की सत्ता में वापसी करना है। इसी बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, "अयोध्या हमारी है, अब मथुरा की बारी है।"

PM मोदी के साथ फिलीपींस में नजर आई ये खूबसूरत लड़की कौन... भारत से क्या है कनेक्शन?



पीएम मोदी सोमवार को दो दिवसीय यात्रा पर फिलीपींस की राजधानी मनीला पहुंचे। जहां पीएम के साथ एक खूबसूरत लड़की नजर आई। जिसके बाद उस फोटो की इंटरनेट पर काफी चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को दो दिवसीय यात्रा पर फिलीपींस की राजधानी मनीला पहुंचे। मनीला इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। पीएम मोदी के फिलीपींस दौरे के दौरान एयरपोर्ट पर उनके साथ एक खूबसूरत लड़की नजर आई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को दो दिवसीय यात्रा पर फिलीपींस की राजधानी मनीला पहुंचे। मनीला इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया।

12 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, 145 की रफ्तार से चलेंगी हवाएं; चक्रवाती तूफान सक्रिय

बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान कितना खतरनाक होगा? आंध्र प्रदेश में 145 किमी की रफ्तार से हवाएं चलने और ओडिशा समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। बं बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवाती तूफान अगले तीन दिनों में गंभीर रूप ले सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, 17 से 19 नवंबर के बीच इसके तेजी से ताकतवर होने और आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ने की संभावना है। इस दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। वहीं, समुद्र में 145 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों और तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। 19



नवंबर तक अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है सिस्टम मौसम विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्व और उससे सटे दक्षिण-पश्चिम हिस्से में बना डीप डिप्रेशन उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके 17 नवंबर की शाम तक गंभीर चक्रवाती तूफान और इसके बाद 19 नवंबर की रात तक अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। इसके आंध्र प्रदेश तट के पास पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने का अनुमान है। गाल की खाड़ी में 19 नवंबर तक अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान बनने का अनुमान, आंध्र प्रदेश तट की ओर बढ़ेगा सिस्टम। आंध्र प्रदेश के तट पर 145 किमी प्रति घंटे और बंगाल की खाड़ी में 145 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है हवाओं की रफ्तार। ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। आंध्र प्रदेश में 145 किमी प्रति घंटे तक चलेंगी हवाएं 17 से 19 नवंबर के दौरान समुद्र में हवा की रफ्तार लगातार बढ़ने का अनुमान है। पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में 18 नवंबर से हवाएं 110-120 किलोमीटर प्रति घंटे और 19 नवंबर से 120-130 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। झोंकों के साथ इनकी रफ्तार 145 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की संभावना है। आंध्र प्रदेश और यनम के तटों के पास 19 नवंबर की रात से 20 नवंबर की दोपहर तक हवा की गति 120-130 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।

सम्पादकीय

सोनिया की आत्मकथा में 'झूठ के साथ किए गए प्रयोग'

साध्वी प्रज्ञा सिंह और कर्नल पुरोहित के मामलों ने यह साबित कर दिया है कि सोनिया गांधी की राजनीतिक यात्रा प्रेम की नहीं, बल्कि नफरत की थी। सोनिया गांधी ने इस झूठे बयान के जरिए अपनी छवि सुधारने की कोशिश की है। हालांकि, उनकी असलियत सामने आ चुकी है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहीं सोनिया गांधी की आत्मकथा हाल ही में प्रकाशित हुई है। अपनी आत्मकथा में, कांग्रेस पार्टी के पतन के लिए जिम्मेदार मानी जाने वाली सोनिया गांधी ने राजनीतिक लाभ के लिए अपने ही परिवार को बदनाम करके अपना क्रूर और विश्वासघाती चेहरा दिखाया है। इस आत्मकथा में, सोनिया गांधी ने गांधी परिवार में शामिल होने के बाद से 2004 से 2014 तक कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के 10 वर्षों के सफर की समीक्षा की है। इस समीक्षा के दौरान, उन्होंने कुछ ऐसी घटनाओं पर भी अपनी राय व्यक्त की है जो इस सफर में कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए एक परीक्षा साबित हुईं। इस राय के माध्यम से, सोनिया गांधी ने झूठ के साथ किए गए अपने प्रयोगों की एक लंबी श्रृंखला प्रस्तुत की है। उन्होंने कुछ घटनाओं पर बेहद स्पष्ट रुख अपनाते हुए खुद को और अपने पति, दिवंगत राजीव गांधी को निर्दोष साबित करने का दावा किया है। इस आत्मकथा में, उन्होंने गांधी परिवार की बहू बनने तक की घटनाओं का वर्णन किया है। चूंकि ये घटनाएं उनके निजी जीवन का हिस्सा हैं, इसलिए इनकी आलोचना करना उचित नहीं होगा। हालांकि, सोनिया गांधी द्वारा राजनीतिक घटनाक्रमों और सरकारी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के संबंध में किए गए खुलासों और व्यक्त किए गए विचारों को ध्यान में रखना आवश्यक है। इस आत्मकथा का सबसे आपत्तिजनक हिस्सा आपातकाल काल पर की गई टिप्पणी है। आपातकाल काल कई कारणों से विवादों से घिरा रहा। आपातकाल के दौरान आम आदमी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलकर और लाखों विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को जेल में डालकर इंदिरा गांधी ने अपने क्रूर तानाशाह रूप को प्रदर्शित किया। इसके अलावा, आपातकाल के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम को जबरन लागू करते हुए सरकारी तंत्र ने अत्याचारों की पराकाष्ठा को छू लिया। हजारों अविवाहित पुरुषों पर परिवार नियोजन की सर्जरी भी की गई। इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी और उनके साथियों विद्याचरण शुक्ला और बंसीलाल को आपातकाल के दौरान हुए अत्याचारों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। इन अत्याचारों के कारण उत्तर भारत में इंदिरा गांधी, संजय गांधी और कांग्रेस के खिलाफ असंतोष की एक बड़ी लहर उठी, जिसके परिणामस्वरूप 1977 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। मतदाताओं ने इंदिरा और संजय गांधी की मायलेकर जोड़ी को नकार दिया। इंदिरा गांधी को भी समय के साथ अपनी गलती का एहसास हुआ। इंदिरा जी ने भी स्वीकार किया कि आपातकाल लगाना उनकी गलती थी। हालांकि, उन्होंने आपातकाल के दौरान हुए अत्याचारों और अन्य अप्रिय घटनाओं की जिम्मेदारी संजय गांधी पर डालने की कोशिश नहीं की। इंदिरा गांधी ने जो कुछ भी हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी स्वीकार की थी। आपातकाल के दौरान सोनिया गांधी राजीव गांधी और उनके बच्चों के साथ विदेश में थीं। 50 साल बीत जाने के बाद भी आपातकाल की कड़वी यादें मिट नहीं पाई हैं। कांग्रेस को आज भी इस मुद्दे पर रक्षात्मक रुख अपनाना पड़ता है। आपातकाल के दौरान तानाशाही के फैसले से कांग्रेस को जो झटका लगा, उसके बाद कई वरिष्ठ नेताओं ने इंदिरा गांधी का साथ छोड़ दिया। संजय गांधी की आकस्मिक मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी अलग-थलग पड़ गईं। ऐसी स्थिति में उन्होंने राजीव गांधी को भारत आमंत्रित किया। राजीव गांधी 10 वर्षों तक सक्रिय राजनीति में रहे। इस दौरान उन्होंने आपातकाल के लिए अपने भाई को दोषी ठहराकर खुद को इससे दूर करने की कोशिश नहीं की। हालांकि, सोनिया गांधी ने आपातकाल की जिम्मेदारी संजय गांधी पर डालकर खुद को बरी कर लिया। उस दौरान दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया था। ये अतिक्रमण मुस्लिम समुदाय के थे। सोनिया गांधी ने अपनी आत्मकथा में बुलडोजर से अतिक्रमण हटाने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। हालांकि, अपने पति के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली और पूरे देश में सिख समुदाय के क्रूर नरसंहार पर उन्होंने खेद का एक शब्द भी नहीं कहा। सोनिया गांधी, जिन्होंने 50 साल पहले तुर्कमान गेट क्षेत्र में हुई घटना के लिए अपने देवर को दोषी ठहराकर मुसलमानों को दोषी ठहराने की कोशिश की थी, हजारों सिख नागरिकों के नरसंहार पर चुप हैं। यह उनका पाखंड दर्शाता है। सोनिया गांधी, जिन्होंने आपातकाल के दौरान संजय गांधी को एक गैर-संवैधानिक सत्ता केंद्र बताया था, यह बात आसानी से भूल गई हैं कि मनमोहन सिंह के 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहने के दौरान वह खुद भी एक गैर-संवैधानिक सत्ता केंद्र बन गई थीं। मनमोहन सिंह के नाममात्र के प्रधानमंत्री होने से जुड़ी कई रोचक कहानियाँ संजय बारू ने अपनी पुस्तक में बताई हैं, जो उस समय मनमोहन सिंह के प्रचार सचिव थे।सोनिया गांधी ने अपनी किताब में बोफोर्स भ्रष्टाचार मामले पर भी चुप्पी साध रखी है, जिसके कारण राजीव गांधी को सत्ता से इस्तीफा देना पड़ा था। उस समय कई खबरें छपी थीं जिनमें मनमोहन सिंह सरकार के दौरान बोफोर्स कांड के मुख्य आरोपी क्वात्रोची को बचाने के प्रयासों का जिक्र था। सोनिया गांधी भी इस पर चुप नहीं हैं। संजय बारू और चित्रा सुब्रमण्यम जैसे जाने-माने पत्रकारों ने सोनिया गांधी के उसी सरकार चलाने के बारे में कई लेख लिखे हैं जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे।

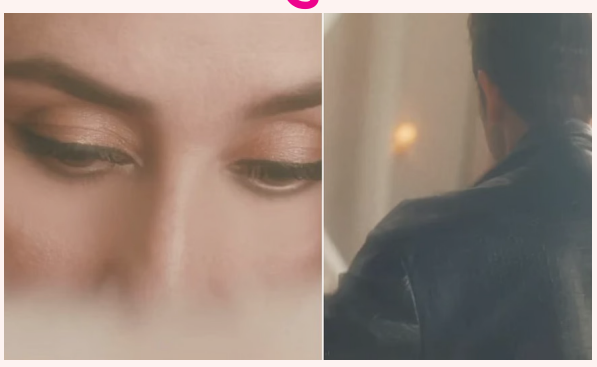
राजनीति की केंद्रीय धुरी बनता हिंदुत्व

स्वाधीनता के बाद से ही भारतीय राजनीति में एक धारा ऐसी रही, जिसका सपना राजनीति के केंद्र में हिंदुत्व लाना रहा। भाजपा के राष्ट्रीय उभार के बाद यह सपना पूरा हुआ। इसके बावजूद राजनीति का बड़ा हिस्सा अब भी सेक्युलरवादी खोल में अल्पसंख्यकवाद केंद्रित राजनीति ही करता है। इसी कारण सेक्युलरिज्म को छद्म सेक्युलरिज्म की संज्ञा मिली। यदि सेक्युलर राजनीति का कोई पैरोकार राम मंदिर जाने की घोषणा करे तो यह मामूली बात नहीं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का 12 दिसंबर को राम मंदिर में दर्शन करने जाना राजनीति में आ रहे बदलाव का प्रतीक है। अखिलेश जिस राजनीतिक धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसकी न तो राम मंदिर निर्माण में भागीदारी रही, न ही वह अयोध्या ढांचा ध्वंस को स्वीकार करती है। फिर भी वे राम मंदिर जा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि अब उन्हें भी अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए हिंदुत्ववादी राजनीति जरूरी लगने लगी है। आज हिंदुत्व की राजनीति का प्रमुख चेहरा भाजपा है, पर स्वाधीनता के बाद की राजनीति में हिंदुत्ववादी राजनीति का चेहरा हिंदू महासभा और स्वामी करपात्री जी की रामराज्य परिषद थी। भाजपा का पूर्ववर्ती संस्करण जनसंघ भी इसी राजनीति की कड़ी रहा। ये दल सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदू समाज के अधिकारों, परंपराओं और मान्यताओं की उपेक्षा करने की तत्कालीन राजनीति के विरोधी रहे। हिंदुत्ववादी धारा की राजनीति सेक्युलरिज्म के बहाने अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति का विरोध करती थी। हालांकि तत्कालीन राजनीति ने तुष्टीकरण के विरोध को अल्पसंख्यक विरोध के रूप में प्रचारित किया। बाद में सेक्युलरवाद ऐसा फैशन बना, जहां हिंदू परंपराओं-मान्यताओं को रूढ़िवादी बताना प्रगतिशीलता मान लिया गया। वर्ष 2014 में हुए आम चुनाव के बाद मोदी और भाजपा के उभार का बड़ा कारण हिंदुत्व की राजनीति भी रही, पर इसे राजनीति की धुरी मानने से राजनीति के बड़े हिस्से को परहेज रहा। तमाम सेक्युलरवादी दलों को भाजपा का यह उभार तात्कालिक लगा और उन्होंने माना कि यह उभार कुछ ही दिनों का मेहमान है, पर तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम जैसे कुछ राज्यों को छोड़ दें तो भाजपा के नेतृत्व में हिंदुत्व की राजनीति गहरा असर दिखाती रही। इसे रोकने में जब भाजपा विरोधी दल नाकाम रहे तो उन्हें मजबूरी में ही सही, हिंदुत्व का खुले-छिपे रूप में सहारा लेना पड़ा। जैसे 2017 के गुजरात और 2018 के कर्नाटक चुनावों के समय राहुल गांधी जनेऊ पहनकर मंदिर-मंदिर गए। गुजरात में वे नाकाम रहे, कर्नाटक में कामयाब। इसके बाद राहुल फिर छद्म सेक्युलरवादी धारा की ओर लौट पड़े। मुलायम सिंह जब पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब भाजपा उनका समर्थन कर रही थी। बाद में उनकी पूरी राजनीति भाजपा विरोधी की रही। 1990 में जब लालकृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर के समर्थन में रथयात्रा शुरू की तो जनता दल के क्षत्रपों और खासकर मुलायम सिंह और लालू यादव में आडवाणी को गिरफ्तार कर मुस्लिम समुदाय का हीरो बनने की होड़ लगी। लालू यादव ने आडवाणी को समस्तीपुर में गिरफ्तार करा दिया। इसके कुछ समय बाद अयोध्या में कारसेवकों पर पुलिस ने गोलियां चलाईं। इस घटना के बाद जहां भाजपा हिंदुत्व की राजनीति के प्रखर पैरोकार के रूप में उभरी, वहीं लालू और मुलायम हिंदुत्व विरोधी राजनीति के प्रमुख चेहरे के रूप में। दोनों अपने-अपने राज्यों में सत्ता के शीर्ष पर भी रहे। राष्ट्रीय राजनीति में नरेन्द्र मोदी के उभार ने छद्म सेक्युलरिज्म की राजनीति के गुब्बारे में पिन चुभोने का काम किया। आज भाजपा विरोधी दलों को यह समझ नहीं आता कि वे भाजपा के हिंदुत्व की पिच पर बल्लेबाजी करें या फिर अपनी पिच खुद बनाएं। अखिलेश की राजनीति देखकर लगता है कि सत्ता से दूरी को पाटने के लिए वे हिंदुत्व की उसी पिच पर उतरने की तैयारी में हैं, जिसे भाजपा ने बनाया है। चूंकि वे इटावा में केदारनाथ मंदिर का प्रतिरूप भी बनवा रहे हैं, इसलिए कह सकते हैं कि वे अपनी तरह की हिंदुत्ववादी राजनीति भी तैयार कर रहे हैं। लालू यादव भी सेक्युलरवादी हैं, लेकिन निजी और पारिवारिक कार्यक्रमों में वे हिंदू परंपराओं को न सिर्फ निभाते हैं, बल्कि उनका जोर-शोर से प्रचार भी करते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय भी मंदिरों में जाते दिखते हैं, जबकि वे ईसाई हैं। इसे हिंदुत्व की राजनीति का असर कहें या कुछ और, कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी विरोधी महबूबा मुफ्ती हाल में क्षीर-भवानी मंदिर गए। कांग्रेस की राजनीति थोड़ी इतर दिखती है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के एक खेमे की चाह है कि राहुल को भी अयोध्या के राम मंदिर जाना चाहिए। वे ऐसा कर भी सकते हैं, लेकिन शायद उनकी राह में मां सोनिया गांधी के आंसू बड़ी बाधा हैं। हाल में अपनी आत्मकथा को लेकर दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बाबरी ढांचे के ध्वंस के वक्त वे रो पड़ी थीं। इसके पहले सलमान खुर्शीद ने बताया था कि दिल्ली के बाटला हाउस मुठभेड़ के बाद भी उनके आंसू निकले थे। यह भविष्य बताएगा कि सेक्युलरवादी दलों की हिंदुत्व की राजनीति कितनी दूर तक जाएगी, लेकिन इतना जरूर है कि सत्ता की राजनीति किसी भी हद तक बदल सकती है।

भरोसेमंद देश के रूप में उभरता भारत

भारत-आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी फिलीपींस की राजधानी मनीला में हैं। 11 देशों के आसियान समूह और उसके चारों ओर फैले क्षेत्र के महत्व को इससे समझा जा सकता है कि अपने 12 वर्षों के कार्यकाल में मोदी 13वीं बार भारत-आसियान शिखर और 10वीं बार पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में सहभागिता कर रहे हैं। चाहे भू-राजनीतिक और सुरक्षा संबंधित हित हों या आर्थिक अवसर, भारत 'एक्ट ईस्ट' नीति के अंतर्गत अपने पूर्वी दिशा के विस्तारित पड़ोस के साथ जुड़ाव बढ़ा रहा है, क्योंकि विश्व समुदाय का ध्यान एक समय शक्ति केंद्र रहे यूरो-अटलांटिक से विमुख होकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र की ओर मुड़ चुका है। भारत 'आसियान केंद्रीयता' का समर्थन करता है। इसका अर्थ है चीन और अमेरिका जैसी महाशक्तियों के द्वंद्व और दांव-पेच के बीच मध्यम और छोटी शक्तियों के गुट को मजबूत करके उन्हें स्वायत्त और खुला रखना। इस उद्देश्य को साधने के लिए भारत ने आसियान के साथ सहयोग के नए आयाम तलाशते हुए संबंधों को निरंतर गहरा किया है। इसी क्रम में 'महासागर सिद्धांत' के तहत भारतीय नौसेना आसियान देशों की नौसेनाओं संग संयुक्त समुद्री सैन्य अभ्यास करने में लगी है। इससे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की नौसैनिक क्षमताओं और तैयारियों में वृद्धि हो रही है। आसियान के पांच देश-ब्रूनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम-का चीन के साथ समुद्री विवाद है और उन्हें चीन के आक्रामक रुख और दबाव का सामना करना पड़ रहा है। चीन की दादागीरी की काट के लिए इन देशों ने अमेरिका से रक्षा संबंध मजबूत तो बनाए हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापारिक सौदेबाजी के फेर में चीन के प्रति नरमी का रुख अपनाकर आसियान के लिए दुविधा पैदा कर दी है। इससे उपजी अनिश्चितता का ही परिणाम है कि फिलीपींस, इंडोनेशिया और वियतनाम ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल और अन्य सैन्य साजोसामान खरीदने का फैसला किया है। जबकि मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार और सिंगापुर भी भारत से सैन्य सामग्री लेने के इच्छुक हैं। तथ्य यह भी है कि 2020 और 2025 के बीच भारत के वैश्विक हथियार निर्यात का 70 प्रतिशत से अधिक हिस्सा आसियान देशों को गया है। इस सबके बावजूद भारत अकेले ही आसियान के लिए सुरक्षा आवरण प्रदान करने में अमेरिका की भरपाई नहीं कर सकता। चीन से प्रताड़ित दक्षिण-पूर्वी एशियाई देश जापान और आस्ट्रेलिया से भी रक्षा सहयोग बढ़ा रहे हैं, ताकि 'क्वाड' चतुर्भुज में अमेरिकी कड़ी कमजोर पड़े तो बाकी तीन कड़ियों का लाभ उठाया जा सके। अमेरिका क्वाड को लेकर प्रतिबद्ध हो या न हो, मगर भारत, जापान और आस्ट्रेलिया की तिकड़ी इस मोर्चे पर सक्रिय है और आसियान के लिए सुरक्षा कवच बनाने में इन तीनों का तालमेल महत्वपूर्ण होगा। क्वाड नेता मनीला में भी मिलेंगे, लेकिन ट्रंप की अपारंपरिक विदेश नीति के चलते भारत के पास चीन के सापेक्ष एक बड़ी भूमिका निभाने का मौका है। भारत आसियान के साथ 2010 से लागू किए गए मुक्त व्यापार समझौते में संशोधन को शीघ्र मूर्त रूप देने के लिए प्रयासरत है। वार्षिक तौर पर 128 अरब डालर के द्विपक्षीय व्यापार में भारत को केवल 38 अरब डालर के निर्यात का अवसर मिलता है, जबकि 89 अरब डालर का सामान आसियान से आयात किया जा रहा है। ट्रंप के व्यापार युद्ध और शुल्क के चलते आसियान चीन के बाजार पर और अधिक निर्भर हो गया है, जो इन देशों की स्वायत्तता और उद्योगों के लिए खतरा है। ऐसे में, भारत के साथ व्यापार समझौते में उदार रवैये और विदेशी निवेश में बढ़ोतरी से दोनों पक्षों को लाभ मिलेगा। बीते दिनों आसियान देशों के बीच डिजिटल अर्थव्यवस्था रूपरेखा समझौता (डेफा) पर हस्ताक्षर होना एक शुभ संकेत है, क्योंकि उसके जरिये भारत डिजिटल भुगतान में अपनी सामर्थ्य के बलबूते सभी 11 देशों के बाजारों में पैठ बना सकता है। भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) को अब तक सिंगापुर और कंबोडिया की वित्तीय प्रणालियों के साथ जोड़ा जा चुका है।

25 साल बाद फिर दिखे ऋतिक-करीना, क्या करण जौहर बनाएंगे कभी खुशी कभी गम पार्ट 2?



करण जौहर ने कभी खुशी कभी गम के 25 साल पूरे होने से पहले ऋतिक रोशन और करीना कपूर की झलक दिखाई है। इस टीजर को देखने के बाद फिल्म के सीक्वल की चर्चाएं तेज हो गई है। 25 साल बाद फिर साथ दिखे ऋतिक रोशन और करीना कपूर करण जौहर ने शेयर किया कभी खुशी कभी गम का खास टीजर सीक्वल की चर्चा तेज, 19 नवंबर को खुलेगा Airbnb कैंपेन का राज साल 2001 में बड़े पर्दे पर धमाल मचाने वाली फिल्म कभी खुशी कभी गम का जादू आज भी बरकरार है। इस फिल्म के डायरेक्टर करण जौहर ने अपने फैंस के लिए एक स्पेशल सरप्राइज पेश किया है। हाल ही में धर्मा प्रोडक्शंस के मालिक और बॉलीवुड डायरेक्टर करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक टीजर शेयर किया है। इस टीजर में करीना और ऋतिक की मशहूर जोड़ी की झलक देखने मिलती है। जिसके बाद से लगातार कभी खुशी कभी गम सीक्वल को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। कुछ कहानियां 25 साल बाद भी खत्म नहीं होतीं करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर टीजर शेयर करते हुए लिखा कि कुछ कहानियां 25 साल बाद भी खत्म नहीं होतीं। इस टीजर वीडियो में ऋतिक रोशन के किरदार रोहन और करीना कपूर के किरदार पूजा यानी पू की झलक दिखाई गई है। इस टीजर के जरिए एक Airbnb कमर्शियल को प्रमोट किया जा रहा है, जिसका पूरा खुलासा 19 नवंबर को किया जाएगा। फैंस को याद आई रोहन और पू की जोड़ी टीजर सामने आते ही सोशल मीडिया पर फैंस के बीच एक्साइटमेंट देखने के लिए मिल रही है। कई यूजर्स ने ऋतिक रोशन और करीना कपूर को एक साथ देखकर खुशी जाहिर की। एक यूजर ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, ऋतिक-करीना साथ में, यह क्या है! वहीं कुछ प्रशंसकों ने दोनों की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री की तारीफ की और फिल्म के सीक्वल की उम्मीद जताई। सीक्वल या खास ब्रांड कोलैबरेशन? टीजर ने दर्शकों के बीच कई तरह के कयासों को जन्म दिया है। कुछ फैंस इसे कभी खुशी कभी गम' के सीक्वल से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि अन्य इसे Airbnb के साथ खास ब्रांड कोलैबरेशन मान रहे हैं। हालांकि, अभी सामने आई जानकारी के अनुसार यह एक प्रमोशनल कैंपेन है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी 19 नवंबर को सामने आएगी। 25 साल बाद भी कायम है फिल्म का जादू करण जौहर के डायरेक्शन में बनी कभी खुशी कभी गम साल 2001 में रिलीज हुई थी। फिल्म में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर खान अहम भूमिकाओं में नजर आए थे। फिल्म के किरदार, गाने और डायलॉग आज भी दर्शकों के बीच फेमस हैं। ऐसे में रोहन और पू की झलक ने एक बार फिर फिल्म को लेकर फैंस का उत्साह बढ़ा दिया है।

काजी तौकीर और मनीष गोयल की हुई जोरदार बहस, आम्रपाली दुबे ने बदला गेम का रुख



बिग बॉस 20 के नए प्रोमो में काजी तौकीर और मनीष गोयल के बीच बहस देखने को मिलेगी। वहीं आम्रपाली दुबे लव गिल से भिड़ती और अपने ट्रिगर पॉइंट के बारे में बताती नजर आएंगी। बिग बॉस 20 के नॉमिनेशन टास्क में काजी-मनीष गोयल के बीच भिड़ंत आम्रपाली दुबे ने पलटा गेम, लव गिल से हुई तीखी बहस आम्रपाली ने बताया अपना ट्रिगर पॉइंट, इल्जामों से होती हैं परेशान कलर्स टीवी के रियलिटी शो बिग बॉस में आज बड़े तमाशे होने वाले हैं। जहां एक ओर नॉमिनेशन की प्रोसेस में कंटेस्टेंट की भड़ास निकलने वाली है, तो वहीं घर वालों में बीच में जोरदार झगड़े होते हुए भी देखने के लिए मिलेंगे। बिग बॉस 20 में कई हफ्तों से लव गिल और स्काउट ओपी का भाई-बहन का रिश्ता सवालों के घेरे में था। जिसके बाद सलमान खान, रोहित शेट्टी, स्काउट ओपी की गर्लफ्रेंड काश्वी हीरचंदानी, आम्रपाली दुबे से लेकर यंग डीएसए तक ने इन दोनों को दूर रहने की हिदायत दी थी।

फराह खान के कुक दिलीप को अनन्या बिरला ने दिया सरप्राइज, गिफ्ट की 1 लाख की लग्जरी घड़ी



अनन्या बिरला ने फराह खान के कुक दिलीप को करीब एक लाख रुपये की लग्जरी घड़ी गिफ्ट की। बिहार के मधुबनी के रहने वाले दिलीप फराह के व्लॉग्स से लोकप्रिय हुए हैं। अनन्या बिरला ने फराह खान के कुक दिलीप को लग्जरी घड़ी गिफ्ट की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस घड़ी की कीमत करीब एक लाख रुपये है। फराह खान अपने कुक दिलीप के साथ अनन्या बिरला के आलीशान घर पहुंची थीं। फि कौ 16 साल की उम्र में छोड़ा था घर दिलीप ने महज 16 साल की उम्र में काम की तलाश में बिहार छोड़ दिया था। शुरुआत में उन्होंने दिल्ली में लोगों के घरों में काम किया और फिर मुंबई पहुंच गए। यहां फराह खान के घर काम मिलने के बाद उनकी जिंदगी बदलने लगी। अप्रैल 2024 में वह पहली बार फराह के कुकिंग व्लॉग में नजर आए थे। धीरे-धीरे उनकी पहचान सोशल मीडिया पर बढ़ती गई और अब वह कई ब्रांड के विज्ञापनों में भी दिखाई देते हैं। न हैं फराह खान के कुक दिलीप दिलीप मुखिया पिछले करीब 13 साल से फराह खान के साथ काम कर रहे हैं। वह बिहार के मधुबनी के रहने वाले हैं। फराह के यूट्यूब व्लॉग्स में नजर आने के बाद उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ गई। फराह और दिलीप की मजेदार बातचीत और नोकझोंक दर्शकों को खूब पसंद आती है। ल्मेकर और कोरियोग्राफर फराह खान इन दिनों अपने यूट्यूब व्लॉग्स को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। वह अक्सर बॉलीवुड सितारों और मशहूर हस्तियों के घर पहुंचती हैं और अपने कुक दिलीप के साथ वहां की दिलचस्प झलक दिखाती हैं। इस बार फराह बिजनेसमैन कुमार मंगलम बिरला की बेटी और सिंगर अनन्या बिरला के घर पहुंचीं। यहां अनन्या ने फराह के कुक दिलीप को ऐसा खास तोहफा दिया, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। अनन्या ने दिलीप को करीब एक लाख रुपये की लग्जरी घड़ी गिफ्ट की। फराह खान हाल ही में अपने कुक दिलीप के साथ अनन्या बिरला के घर पहुंचीं। इस दौरान उन्होंने अपने व्लॉग में अनन्या के आलीशान घर की झलक दिखाई। घर का शानदार इंटीरियर, खूबसूरत सजावट और लग्जरी सुविधाएं देखकर फराह भी इसकी तारीफ करती नजर आईं। घर का शाही अंदाज देखकर फराह और दिलीप दोनों काफी प्रभावित हुए। दिलीप को मिला करीब एक लाख रुपये का तोहफा इस मुलाकात का सबसे खास पल तब आया, जब अनन्या बिरला ने फराह खान के कुक दिलीप को एक लग्जरी घड़ी गिफ्ट की। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस घड़ी की कीमत करीब एक लाख रुपये बताई जा रही है। इतना महंगा तोहफा पाकर दिलीप काफी खुश नजर आए। फराह के व्लॉग में यह पूरा पल देखने को मिला। सोशल मीडिया पर भी लोग अनन्या के इस व्यवहार की तारीफ कर रहे हैं।

लॉस एंजिल्स में खेल सकता है भारत? अगले साल जुलाई में वेस्टइंडीज के खिलाफ अमेरिका या कनाडा में होंगे T20 मैच



भारत अगले साल जुलाई 2027 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अमेरिका या कनाडा में दो T20 मैच खेल सकती है। इन मैचों की मेजबानी के लिए वाशिंगटन डीसी व टोरंटो सबसे आगे चल रहे हैं। 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक से एक साल पहले टीम इंडिया को वहां खेलने का मौका मिल सकता है। जुलाई 2027 में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो टी20 मैच खेले जा सकते हैं। वेस्टइंडीज की मेजबानी में ये मुकाबले अमेरिका या कनाडा में आयोजित होने की संभावना है। भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम को साल 2028 में होने वाले लॉस एंजिल्स ओलंपिक से ठीक एक साल पहले वहां खेलने का सुनहरा मौका मिल सकता है।

कतर पहुंची भारतीय क्रिकेट टीम, 22 नवंबर को पाकिस्तान से होगा महामुकाबला



राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए तिलक वर्मा की कप्तानी में इंडिया ए की टीम दोहा पहुंच गई है। 19 नवंबर से शुरू होने वाले इस वनडे टूर्नामेंट में रोमांच देखने को मिलने वाला है। राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए भारतीय ए टीम पहुंची दोहा 19 नवंबर से शुरू होने जा रहा है राइजिंग स्टार्स एशिया कप। इस टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम कतर की राजधानी दोहा पहुंच गई है। क्रिकेट फैंस के लिए एक और बड़े टूर्नामेंट का आगाज होने जा रहा है। 19 नवंबर से शुरू हो रहे राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2026 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम (इंडिया ए) कतर की राजधानी दोहा पहुंच गई है। मंगलवार, 17 नवंबर को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सोशल मीडिया पर अपडेट साझा कर टीम के दोहा पहुंचने की पुष्टि की। युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम की कमान संभालते नजर आएंगे। वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह पर रहेंगी नजरें वनडे फॉर्मेट में खेले जाने वाले इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के लिए भारत ने एक बेहद संतुलित और विस्फोटक स्क्वाड का चयन किया है। टीम में युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी और तूफानी ओपनर अभिषेक शर्मा को शामिल किया गया है, जिनसे फैंस को आक्रामक शुरुआत की उम्मीद होगी। इसके अलावा मध्यक्रम को मजबूती देने के लिए फिनिशर रिंकू सिंह, प्रभसिमरन सिंह और सूर्यांश शेडगे जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी भी टीम का हिस्सा हैं। हर्षित राणा की वापसी, रजत पाटीदार हुए बाहर तेज गेंदबाज हर्षित राणा लंबे समय के बाद मैदान पर वापसी करने जा रहे हैं। सीनियर टीम इंडिया में दोबारा जगह बनाने के लिहाज से हर्षित के लिए यह टूर्नामेंट बेहद अहम साबित होगा। वहीं, अनुभवी बल्लेबाज रजत पाटीदार भी पहले इस स्क्वाड का हिस्सा थे, लेकिन चोटिल होने के कारण उन्हें टूर्नामेंट से अपना नाम वापस लेना पड़ा।

मनीला में PM मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की मुलाकात, कई अहम मुद्दों प हुई चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनीला में सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग से मुलाकात कर रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा की। मनीला में पीएम मोदी और लॉरेंस वोंग के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। मोदी ने सिंगापुर को आगामी ASEAN अध्यक्षता के लिए शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित 21वें ईस्ट एशिया समिट के दौरान सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया। विदेश मंत्रालय ने इस बैठक को 'गर्मजोशी भरी और सार्थक' बताया। बैठक के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत अब तक हुए कामकाज का जायजा लिया और द्विपक्षीय सहयोग को और अधिक मजबूत बनाने के संभावित तरीकों पर चर्चा की। मोदी ने ASEAN बैठक के लिए सिंगापुर को दी शुभकामनाएं विदेश मंत्रालय के अनुसार, दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए। इसके साथ ही भारत और सिंगापुर के बीच लंबे समय से कायम



मजबूत संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ASEAN की आगामी अध्यक्षता के लिए सिंगापुर को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग को इस जिम्मेदारी के लिए भारत की ओर से पूर्ण सहयोग का भरोसा भी दिलाया। सिं कई अहम क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रहे रिश्ते भारत और सिंगापुर के बीच व्यापार एवं निवेश, रक्षा और सुरक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, हरित ऊर्जा, कौशल विकास तथा कनेक्टिविटी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंगापुर यात्रा के दौरान दोनों देशों के संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। यह कदम भारत और सिंगापुर के बीच बढ़ते आपसी विश्वास और मजबूत होते द्विपक्षीय संबंधों को दर्शाता है। सिंगापुर दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत के प्रमुख आर्थिक और रणनीतिक साझेदारों में शामिल है। इसके अलावा, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और व्यापक इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के साथ जुड़ाव को आगे बढ़ाने में भी सिंगापुर की महत्वपूर्ण भूमिका है। ASEAN-भारत और ईस्ट एशिया समिट के दौरान हुई मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी और लॉरेंस वोंग की यह बैठक मनीला में आयोजित ASEAN-भारत समिट और 21वें ईस्ट एशिया समिट के दौरान हुई। इन बैठकों में दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत के संबंधों को और मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया। गापुर की आगामी ASEAN अध्यक्षता से भारत और सिंगापुर के बीच क्षेत्रीय सहयोग, आर्थिक एकीकरण और साझा रणनीतिक प्राथमिकताओं को लेकर आपसी समन्वय बढ़ने की उम्मीद है। इससे दोनों देशों को क्षेत्रीय स्तर पर मिलकर काम करने के नए अवसर भी मिलेंगे। इसके साथ ही भारत ने स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियमों पर आधारित इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई।

PM मोदी के फिलीपींस दौरे से 3 बड़े फायदे, जानें कैसे चीन की बढ़ेगी मुश्किलें?

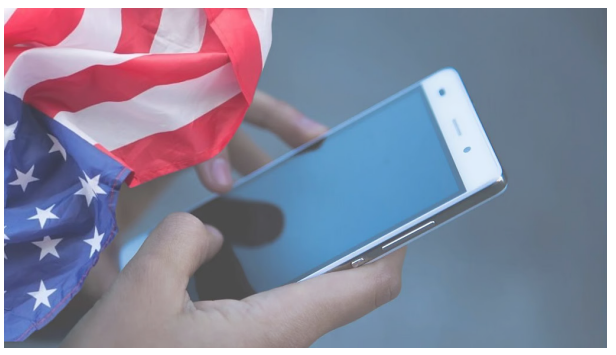




पीएम मोदी के फिलीपींस दौरे से भारत को रक्षा, व्यापार और समुद्री सुरक्षा में क्या फायदे होंगे? चीन पर कितना दबाव बढ़ेगा और क्या ट्रंप से मुलाकात होगी? पीएम मोदी के फिलीपींस दौरे से भारत को रक्षा सहयोग, 122 अरब डॉलर के व्यापार और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक मजबूती के अवसर मिलेंगे। ब्रह्मोस मिसाइल समझौते और दक्षिण चीन सागर में समुद्री सहयोग से चीन के बढ़ते प्रभाव को चुनौती मिल सकती है। क्वाड शिखर सम्मेलन के बीच ट्रंप-मोदी की संभावित मुलाकात से भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता और रक्षा साझेदारी को नई गति मिल सकती है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दो दिवसीय फिलीपींस दौरा भारत की विदेश नीति के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। 17 नवंबर को होने वाले इस दौरे में पीएम मोदी 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता, व्यापार और रक्षा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी है। भारत के लिए यह दौरा सिर्फ दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ संबंध मजबूत करने तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत करने का भी अवसर है। खासतौर पर चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच भारत की सक्रियता के कई मायने निकाले जा रहे हैं। आइए समझते हैं कि पीएम मोदी के इस दौरे से भारत को कौन से तीन बड़े फायदे हो सकते हैं और चीन पर इसका क्या असर पड़ेगा। चीन के मुकाबले हिंद-प्रशांत क्षेत्र में मजबूत होगी भारत की रणनीतिक स्थिति भारत और आसियान देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग इस दौरे का प्रमुख एजेंडा है। दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते दखल और क्षेत्रीय विवादों के बीच भारत दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना चाहता है।

अमेरिका में अब बैंकिंग सेवा और यूनाइटेड एयरलाइंस का नेटवर्क ठप, कई बड़े बैंकों में आई गड़बड़ी

अमेरिका के कई बड़े बैंकों जैसे बैंक ऑफ अमेरिका, चेज, जेपी मॉर्गन, वेल्स फार्गो और Zelle के ग्राहकों ने ऑनलानि सेवाओं में दिक्कतों की शिकायत की। अमेरिका के कई बड़े बैंकों में ऑनलाइन सर्विस ठप बैंक ऑफ अमेरिका, चेज, जेपी मॉर्गन आदि की सर्विस ठप यूनाइटेड एयरलाइंस का नेटवर्क भी ठप हुआ अमेरिका में एक के बाद एक तकनीकी कमी आखिर क्यों सामने आ रही है। पहले माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी में आउटेज की समस्या आई, जिस वजह से वैश्विक स्तर पर कंपनियों का काम ठप हो गया। इतना ही नहीं इसके बाद FAA के एयर ट्रैफिक कंट्रोल नेटवर्क में खराबी के कारण भी 2 दिनों तक अमेरिकी उड़ाने प्रभावित रहीं। अब फिर से यहां बैंकिंग सेवा और यूनाइटेड एयरलाइंस का नेटवर्क ठप हो गया है। अमेरिका के कई बड़े बैंकों में आई गड़बड़ी अमेरिका में अचानक लाखों लोगों की ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं अटक गईं। संयुक्त राज्य अमेरिका



के सबसे बड़े बैंक जेपीमॉर्गन चेस के सिस्टम में सॉफ्टवेयर बग ने कामकाज रोक दिया। चेस के साथ-साथ बैंक ऑफ अमेरिका, वेल्स फार्गो, यूएस बैंक और जेल के कस्टमर्स को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बैंकों की इन सर्विसेज में आ रही दिक्कतें अमेरिकी लोगों को ऑनलाइन अकाउंट खोलने, अपना बैलेंस चेक करने, ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों को चेस ऐप में मैसेज मिला कि कुछ सेवाएं अभी उपलब्ध नहीं हैं, हम उन पर काम कर रहे हैं। कृपया कुछ देर बाद ट्राय करें। इतना ही नहीं चेस ने X पर एक पोस्ट में बताया कि उसके अंदरूनी हार्डवेयर सिस्टम में सॉफ्टवेयर बग के कारण लेनदेन में देरी हुई। यह साइबर हमला नहीं था। 8.6 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स हो रहे प्रभावित दरअसल, अमेरिकी बैंकिंग सर्विस की बात करें तो अकेले जेपीमॉर्गन चेस के 8.6 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स हैं जिन्हें ऑनलाइन बैंकिंग में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

थाइलैंडः चार मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग लगने से 11 की मौत 36 घायल; जांच शुरू



थाइलैंड के फुकेत में आग लग गई। आग किराए पर मोटरसाईकिल देने वाली दुकान में लगी और देखते ही देखते यह आग आसपास के इमारतों में फैल गई। आग फैलने के कारण 11 लोगों की मौत और 36 लोग घायल हैं। थाईलैंड के पर्यटन शहर फुकेत में लगी भीषण आग चार मंजिला इमारत में आग लगने के कारण 11 लोगों की मौत 36 घायल किराये पर देने वाली मोटरसाइकिल दुकान में लगी आग, फैलते-फैलते आसपास के इमारतों में फैली आग सोमवार 16 नवंबर की सुबह थाईलैंड के पर्यटन शहर फुकेत में एक भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। यहां पातोंग इलाके में मोटरसाइकिल किराये पर देने वाली दुकान और उससे जुड़ी व्यावसायिक इमारतों में आग फैल गई।

पाकिस्तान को मिला दिल्ली आने का न्यौता, कांग्रेस बोली- पहलगाम हमले के बाद क्या बदला?

पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने SCO कार्यक्रम में पाकिस्तान को न्योता क्यों दिया? पाकिस्तानी मंत्री की मंजूरी से देश में सियासी विवाद क्यों छिड़ा? भारत ने 20 से 22 नवंबर तक दिल्ली के पुराना किला में होने वाले SCO कार्यक्रम के लिए पाकिस्तान को न्योता दिया। पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक भारत आने वाले हैं। कांग्रेस ने सरकार की पाकिस्तान नीति पर सवाल उठाए। भाजपा ने न्योते का बचाव किया। जानिए SCO में भारत-पाकिस्तान की सदस्यता और आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का रुख। भारत की ओर से पाकिस्तान को शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सभ्यतागत संवाद कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता देना और पाकिस्तान का इसे स्वीकार करना देश में राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया



है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की पाकिस्तान नीति पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का कहना है कि पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आखिर ऐसा क्या बदल गया कि पाकिस्तान के मंत्री को भारत आने का निमंत्रण दिया गया? वहीं, भाजपा ने इस पहल को भारत के हित में बताते हुए पाकिस्तान को आतंकवाद छोड़कर संबंध सुधारने की सलाह दी है। पाकिस्तान ने शनिवार को घोषणा की कि उसके जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक भारत में आयोजित होने वाले SCO कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यह आयोजन 20 से 22 नवंबर तक दिल्ली के ऐतिहासिक पुराना किला में होगा। पहली बार कब और क्यों दिया गया पाकिस्तान को न्योता? भारत ने 28 अक्टूबर को घोषणा की थी कि SCO के सभी सदस्य देशों को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया है।

इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। सरकार के मुताबिक, यह कदम संगठन की स्थापित परंपरा के अनुरूप है। हालांकि, पिछले साल मई में ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह संभवतः पहला मौका है, जब भारत ने किसी पाकिस्तानी मंत्री को अपने यहां आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया है। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत की सैन्य कार्रवाई थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक, इस कार्यक्रम में SCO सदस्य देशों के प्रतिनिधि सभ्यतागत संवाद और सांस्कृतिक समझ से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ...शेष 7 पर

25 साल में 1 लाख मजदूरों में सिर्फ

15 वर्षों से सिर्फ जीआर और आश्वासनों के जरिए गुमराह कर रही है। 15 मार्च 2024 के सकारात्मक आदेश के बाद 7 अक्टूबर 2026 को एमएमआरडीए के बाहर जिलेवार घर देने और फिर 19 अक्टूबर 2026 को एमएमआरडीए क्षेत्र में घर देने के विरोधाभासी आदेशों से भ्रम पैदा हुआ है। मजदूरों ने सवाल उठाया कि मुंबई शहर को खड़ा करने वालों को बाहर क्यों धकेला जा रहा है। मिल मजदूर नेताओं ने चेतावनी दी कि यह लड़ाई उनके सम्मान और न्याय की है और प्रत्यक्ष घर निर्माण शुरू न होने पर आंदोलन अधिक उग्र होगा। वांगणी जाने को तैयार नहीं, कुछ शेलू के लिए सहमत समिति की ओर से कहा गया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीडीडी चॉल कार्यक्रम में - मूल मुंबईकरों को शहर से बाहर न जाने देने का आश्वासन दिया था, लेकिन इसके विपरीत म्हाडा मिल मजदूरों के लिए मुंबई से बाहर शेलू और वांगणी में निजी विकासको के जरिए घर बना रही है। अब तक म्हाडा ने करीब 15 हजार और कोन-पनवेल में लगभग 2,400 घर दिए हैं। यातायात सुविधा न होने से मजदूर वांगणी जाने को तैयार नहीं है, जबकि रेलवे स्टेशन पास होने से कुछ शेलू के लिए सहमत है। इस मुद्दे पर संगठनों में मतभेद से मजदूरों के विस्थापन का खतरा बढ़ गया है। राज्य सरकार एक भी मिल मजदूर घर से वंचित न रहे, ऐसी ठोस कार्ययोजना तैयार करे। केवल नए जीआर निकालने के बजाय प्रत्यक्ष रूप से घर निर्माण और घर आवंटन की शुरुआत करे। मुं मुं रिपेयरिंग बोर्ड, एसआरए, धारावी पुनर्विकास, मिलों की पुरानी वालों और म्हाडा की 56 कॉलोनियों के पुनर्विकास में एक एफएसआई बढ़ाकर अतिरिक्त घर दिए जाएं। एनटीसी के पास उपलब्ध 7 लाख टीडीआर का उपयोग मजदूरों के आवास के लिए किया जाए। न्यू ग्रेट मिल और संप्रग मिल के तैयार घरों की लॉटरी तुरंत निकाली जाए और वंचित मजदूरों को दोबारा आवेदन का मौका मिले। घर आवंटन के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर उसे कानून का रूप दिया जाए। बई में ही सवा लाख घर बनाना संभव गोविंदराव मोहिते और अन्य पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सरकार इच्छाशक्ति दिखाए, तो 2 वर्षों में मुंबई के भीतर 1 लाख 25 हजार मजदूरों को घर देना संभव है। समिति की प्रमुख मांगें केंद्र सरकार से एनटीसी मिलों की जमीन राज्य सरकार अपने कब्जे में लेकर वहां घर बनाए।

बागी हिंदुस्तान 1857 और लहू बोलना भी है किताबों का भव्य विमोचन समारोह 28 नवंबर को दिल्ली में

धनपुरी (शहडोल)। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास, उसमें विभिन्न नायकों के योगदान और 1857 के महासंग्राम कि अनकही कहानियां को सामने लाने वाली दो चर्चित पुस्तके बागी हिंदुस्तान 1857 और लहू बोलना भी है (दूसरा रिवाइज्ड एडिशन उर्दू) का आगामी 28 नवंबर 2026 को भव्य विमोचन सेमिनार हॉल एवाने गालिब, ग़ालिब इंस्टीट्यूट, माता सुंदरी रोड नई दिल्ली में शनिवार को दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक किया जाएगा। इस साहित्यिक अनुष्ठान में देश के कई प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी इतिहासकार और सम्मानित अतिथि अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉ अशोक कुमार पांडे, प्रोफेसर राजकुमार जैन, सुरेश खैरनार, रघु ठाकुर, संजय सिंह, गौहर रजा, टी. गोपाल सिंह, समीर सिद्दीकी जैसी शख्सियतें उपस्थित रहेगी। यह आयोजन इतिहास प्रेमियों, शोधकर्ताओं और देश के स्वतंत्रता संग्राम के वास्तविक इतिहास के जानने के इच्छुक पाठकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है आयोजकों द्वारा सभी साहित्य प्रेमियों और पाठकों से इस इस गरिमामयी समारोह में सम्मिलित होने की विनम्र अपील की गई है। इन दोनों महत्वपूर्ण पुस्तकों के लेखक एवं संपादक श्री सैयद शाहनवाज अहमद कादरी साहब है और बागी हिंदुस्तान 1857 में सहायक संपादक के रूप में श्री गोपाल गोयल जी ने सहयोग किया है। पुस्तकों का परिचय बागी हिंदुस्तान 1857 यह पुस्तक 1857 की अनकही गाथा और स्वाभिमान के पहले महासंग्राम की पूरी कहानी को प्रमाणिक दस्तावेजों और गहरे शोध के साथ प्रस्तुत करती है यह कृति हमें उन ऐतिहासिक प्रसंगों से रूबरू कराती है जो मुख्य धारा के इतिहास में दब गए थे या जिन्हें यथोचित स्थान नहीं मिल पाया था उन सब का प्रमाणिक विवरण प्रस्तुत करती है। लहू बोलता भी है लहू बोलना भी है (दूसरा रिवाइज्ड एडिशन उर्दू) हिंदी इंग्लिश के बाद उर्दू में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मुसलमानों के योगदान और कुर्बानियों के ऐतिहासिक दस्तावेजों पर आधारित है यह पुस्तक अपने दूसरे संशोधित संस्करण में आ रही है यह पुस्तक देश की आजादी के दिए गए बलिदानों की दास्तान बयान करती है और इतिहास के कई अनछुए पहलुओं पर प्रकाश डालती हैं। साजिदखान हज्जन जुबेदा बी मीडिया ग्रुप धनपुरी

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

उदयान विभाग

दुसरा मजला, प्रभाग समिती क्र. ०४, कै. विलासराव देशमुख भवन,
जांगिड इन्क्लेव्ह, कनकिया, मिरारोड (पुर्व)ता.जि.ठाणे - ४०१ १०७ , दुरध्वनी - २८१०३४०९

जा.क्र.मनपा/उदयान/ १२६७/२०२६-२७ **दिनांक :- १७/११/२०२६**

// जाहीर निविदा सुचना //

मिरा भाईंदर महानगरपालिका उदयान विभागामार्फत खालील कामांकरिता दोन लिफाफा पध्दतीने दि.२५/११/२०२६ रोजी दुपारी ०१.०० वाजेपर्यंत मोहरबंद निविदा मागविण्यात येत आहेत. सदर कामाची अटीशर्तीसह निविदा N.I.C. (National informatics Centre, Pune) च्या https://mahatenders.gov.in संकेत स्थळावर उपलब्ध असुन सदर निविदा फॉर्म दि.१८/११/२०२६ पासुन ते दि.२५/११/२०२६ रोजी दुपारी ०१.०० वाजेपर्यंत (डाऊनलोड करुन) भरता येतील. मुदतीत आलेल्या निविदा दि.२७/११/२०२६ रोजी दुपारी ०१.०० वाजता उपस्थित निविदाधारक अथवा त्यांचे प्रतिनिधी यांचे समक्ष निविदा सेल मिरा भाईंदर महानगरपालिका येथे उघडण्यात येतील.

अ.क्र.	कामाचे नाव	अंदाजित खर्च	निविदा बयाणा रक्कम	निविदा फॉर्म फी
१	मिरा भाईंदर महानगरलिका क्षेत्रात शासकीय कार्यक्रम दिना निमित्त महापुरुषांच्या पुतळ्यास फुलांची आरस करणे. (कालावधी – ०२ वर्ष)	रु.५०,००,०००/- (रु. पन्नास लाख मात्र)	रु.५०,०००/- (रु.पन्नास हजार मात्र)	रु.१०००+ १८० (GST) = रु.१,१८०/- (रु. एक हजार एकशे ऐंशी मात्र) (ना- परतावा)

टिप :- १. निविदा दोन लिफाफा पध्दतीने सादर कराव्यात.
२. निविदा फॉर्म फि परत केली जाणार नाही.
३. आलेल्या निविदा मधील कोणतीही एक निविदा स्विकारण्याचा किंवा सर्वच निविदा नाकरण्याचा अधिकार महानगरपालिकेने राखुन ठेवलेला आहे. त्याबददल कोणतेही स्पष्टीकरण दिले जाणार नाही.
४. निविदा विधी ग्राहयता कालावधी १२० दिवसांचा असेल.

सही/-
(कविता बोरकर)
उप-आयुक्त (उद्यान)
मिरा भाईंदर महानगरपालिका

जा. क्र. मनपा/मावाज/ E-१०१९०६८८ /२०२६-२७
दि. १७/११/२०२६

पृष्ठ 1/8 का शेष

भिवंडी जिला न्यायालय के 125 से

बार काउंसिल ने भी समाधान के लिए सकारात्मक पहल पर दिया जोर महाराष्ट्र एवं गोवा बार काउंसिल के अध्यक्ष हर्षल पाटील ने कहा कि न्यायालयीन व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने में कर्मचारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उनकी समस्याओं और मांगों पर उचित स्तर पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने संबंधित पक्षों के बीच सकारात्मक बातचीत के जरिए इस विवाद का समाधान निकालने की जरूरत बताई। वहीं, अधिवक्ता शैलेश गायकवाड ने कहा कि न्यायालयीन कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। हड़ताल का सीधा असर न्यायिक कामकाज के साथ आम नागरिकों पर भी पड़ता है। इसलिए सरकार और संबंधित विभाग को जल्द हस्तक्षेप कर समाधान निकालना चाहिए। फिलहाल 125 से अधिक कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से भिवंडी जिला न्यायालय की न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। अब सभी की नजर राज्य सरकार के रुख पर टिकी है।

अजब गजब 9 लाख की बोलेरो पर

नियम-कायदों को ताक पर रखकर एक ही ठेकेदार को बार-बार काम क्यों दिया गया? प्रो. डी. एन. खरे ने कहा है कि इस पूरे खर्च के पीछे की तकनीकी और वित्तीय प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच होना बेहद जरूरी है। विशेषज्ञ समिति और ACB से जांच की मांग शिकायत में मांग की गई है कि संबंधित वाहनों की लॉगबुक, वर्क ऑर्डर, एस्टीमेट (अंदाजपत्रक), बिल, स्पेयर पार्ट्स रिकॉर्ड, पेमेंट फाइलों और मंजूरी प्रक्रिया की बारीकी से जांच की जाए। साथ ही, एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित कर वाहनों का भौतिक निरीक्षण (Physical Inspection) कराया जाए और आवश्यकता पड़ने पर विजिलेंस या भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) से इसकी जांच कराई जाए। प्रो. डी. एन. खरे ने स्पष्ट मांग की है कि यदि जांच में सार्वजनिक धन का दुरुपयोग, नियमों का उल्लंघन या आर्थिक अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदार के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए आपराधिक मामला (FIR) दर्ज किया जाए और जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए।

भिवंडी में ऑनलाइन जुए के

और बैंक खाताधारकों की जानकारी का इस्तेमाल कर ऑनलाइन गेम खेलने वाले लोगों के साथ धोखाधड़ी की जाती थी। आरोपी कथित तौर पर बुकी और खिलाड़ियों के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड तैयार कर उपलब्ध कराते थे, ताकि ऑनलाइन जुए का कारोबार चलाया जा सके। पुलिस के मुताबिक, इस नेटवर्क में Anna, WOLF, d2tlive/dashboard और GetiD नाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा था। इन प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन जुआ खेलने और खिलाने की गतिविधियां संचालित होने का आरोप है। इस मामले में कुणाल मनोज कर्नल (18), जयप्रकाश त्रिभुवन यादव (18), धनराज धामण (25), भोज सीताराम ठाकुर (25), राहुल कुमार ईश्वरी प्रसाद साहू (22), ऋषभ सोमनाथ सुखदेवे (30), सनी दणिराम साहू (24), संजय परदेशी माणिपुरी (24), विष्णु कुमार पंचराम साहू (18), समीर श्याम पांडे (21) और रामकृष्ण पुरणलाल कुंभकार (19) को गिरफ्तार किया गया है। नारपोली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 336(2), 336(3), 340(2), 3(5), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66(C), 66(D), महाराष्ट्र जुआ अधिनियम की धारा 4 और 5 तथा ऑनलाइन गेमिंग कानून 2025 की धारा 5 और 7 के तहत मामला दर्ज किया है। पूरे मामले की जांच पुलिस निरीक्षक अतुल अदुरकर कर रहे हैं। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों, बैंक खातों, सिम कार्ड और ऑनलाइन लेन-देन की जानकारी जुटा रही है।

बालासाहेब ठाकरे की सच्ची विरासत

एकनाथ शिंदे ने अपने सहयोगियों के साथ हिंदूहृदयसम्राट एवं शिवसेना प्रमुख स्व. बालासाहेब ठाकरे की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बालासाहेब ठाकरे के हिंदुत्व के विचारों और '80 प्रतिशत समाजनीति तथा 20 प्रतिशत राजनीति' के मूलमंत्र को शिवसेना आज भी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ा रही है। बालासाहेब की विचारधारा से प्रेरित होकर महाराष्ट्र सरकार आम जनता के हित में लगातार फैसले ले रही है और समाजकारण को प्राथमिकता दे रही है। हम संकटग्रस्तों के दरवाजे तक शिवसेना एकनाथ शिंदे ने कहा कि हर साल की तरह इस बार भी बालासाहेब के निष्ठावान शिवसैनिक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। बालासाहेब की सीख थी कि कार्यकर्ता घर में नहीं, बल्कि लोगों के दरवाजे पर दिखाई देना चाहिए। इसी विचार को आत्मसात करते हुए शिवसैनिक आज सूखे और संकट से जूझ रहे किसानों के खेतों तक पहुंचकर उनकी समस्याएं, दुख और परेशानियां समझ रहे हैं। 'जहां संकट, वहां शिवसेना' की सीख पर काम उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि बालासाहेब ठाकरे और धर्मवीर आनंद दिघे की सीख थी कि जहां संकट हो, वहां शिवसेना और जहां आपदा हो, वहां शिवसेना सबसे पहले पहुंचनी चाहिए। इसी विचार को व्यवहार में उतारते हुए राज्य के सभी सूखाग्रस्त क्षेत्रों में किसानों की मदद करने के निर्देश शिवसेना के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, विधायकों, सांसदों और मंत्रियों को दिए गए हैं।
संकट की इस घड़ी में किसानों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए संगठन लगातार काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमने किसानों को भरोसा दिया था कि उनकी दिवाली काली नहीं होने देंगे और इस वादे को पूरा करने के लिए सरकार प्रयासरत है। सरकार की ओर से किसानों को तत्काल 5 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है। इसके अलावा शिवसेना की ओर से भी दिवाली सहायता प्रदान की गई है। किसानों के साथ यह सहयोग आगे भी जारी रहेगा।

भिवंडी जिला न्यायालय के 125 से अधिक कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, 'समान काम-समान वेतन' की मांग

हड़ताल से न्यायिक कामकाज प्रभावित, 1,675 मामलों की सुनवाई पर संकट; वादी-प्रतिवादियों और अधिवक्ताओं की बढ़ेंगी मुश्किलें

सिटी न्यूज़ मुंबई/गनी खान भिवंडीः 'समान काम-समान वेतन' की मांग को लेकर भिवंडी जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय के 125 से अधिक कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। महाराष्ट्र के दुय्यम न्यायालयों में कार्यरत कर्मचारियों को उच्च न्यायालय के कर्मचारियों की तर्ज पर संशोधित वेतनमान देने की मांग को लेकर शुरू हुए इस आंदोलन से न्यायालय का कामकाज प्रभावित होने लगा है। कर्मचारियों ने न्यायालय परिसर में धरना देकर राज्य सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। आंदोलनकारी कर्मचारियों का कहना है कि दुय्यम न्यायालयों में काम करने वाले कर्मचारी भी उच्च न्यायालय के कर्मचारियों की तरह ही जिम्मेदारियां निभाते हैं। इसके बावजूद वेतनमान और सुविधाओं में अंतर किया जा रहा है। कर्मचारी संगठन की मांग है कि समान प्रकृति का काम करने वाले सभी कर्मचारियों को समान वेतनमान का लाभ दिया जाए। संगठन ने साफ किया है कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक



हड़ताल जारी रहेगी। कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का सीधा असर न्यायिक व्यवस्था पर पड़ने की आशंका है। बताया जा रहा है कि करीब 1,675 न्यायालयीन मामलों की सुनवाई और उनसे जुड़ी प्रशासनिक प्रक्रियाएं प्रभावित हो सकती हैं। इससे न्यायालय में सुनवाई के लिए आने वाले वादी-प्रतिवादियों, पक्षकारों और अधिवक्ताओं की परेशानी बढ़ सकती है। पहले से लंबित मामलों में सुनवाई टलने से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को और इंतजार करना पड़ सकता है। न्यायालय के वरिष्ठ लिपिक जालंधर रामकृष्ण पाटील ने कहा कि दुय्यम न्यायालयों के कर्मचारी भी न्यायिक व्यवस्था का अहम हिस्सा हैं। वे उच्च न्यायालय के कर्मचारियों की तरह ही अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। ऐसे में उन्हें भी संशोधित वेतनमान का लाभ मिलना चाहिए। इस मांग को लेकर कर्मचारी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं निकलने के कारण उन्हें अनिश्चितकालीन हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा है। वरिष्ठ लिपिक रेशमा अमोल निकते ने कहा कि कर्मचारियों की मांग अनुचित नहीं है। समान काम करने वाले कर्मचारियों के साथ वेतनमान के मामले में भी समान व्यवहार होना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार इस मांग पर गंभीरता से विचार कर जल्द फैसला लेगी, ताकि न्यायालय का कामकाज दोबारा सामान्य हो सके। ...शेष 7 पर

शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म, 23 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार

पानी पीने के बहाने सुनसान कमरे में बुलाकर किया शोषण; अदालत ने 18 नवंबर तक पुलिस हिरासत

सिटी न्यूज़ मुंबई/गनी खान भिवंडी के शांतिनगर इलाके में शादी का झांसा देकर 16 वर्षीय नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने के आरोप में पुलिस ने 23 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान नाजिम हाशिम अंसारी के रूप में हुई है। शांतिनगर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे धरदबोचा है। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने नाबालिग लड़की को पानी पिलाने के बहाने एक सुनसान पड़े कमरे में बुलाया और शादी का झांसा देकर अगस्त से 12 नवंबर के बीच उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। इस दौरान आरोपी ने कथित तौर पर 4 से 5 बार वारदात को अंजाम दिया।इस मामले की जानकारी पीड़िता की मां को होने के बाद शांतिनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(ड) तथा पॉक्सो अधिनियम 2012 की संबंधित धाराओं 4(1), 6(1), 8 और 12 के तहत मामला दर्ज किया है।गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां अदालत ने उसे 18 नवंबर तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया। मामले की आगे की जांच पुलिस उपनिरीक्षक महेश धोंडे कर रहे हैं।

अजब गजब 9 लाख की बोलेरो पर 16 लाख और एक बुलेट की रिपेयरिंग पर 4.28 लाख खर्च! वसई विरार मनपा का कारनामा

विरार । प्रतिनिधि वसई-विरार शहर महानगरपालिका के अग्निशमन विभाग के वाहनों की मरम्मत पर पिछले तीन वर्षों में 4.17 करोड़ से अधिक खर्च होने का गंभीर मामला सामने आया है। इस पूरे प्रकरण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए प्रो. डी. एन. खरे ने महानगरपालिका आयुक्त से मामले की गहन जांच और विशेष ऑडिट (Special Audit) कराने की मांग की है। प्रो. डी. एन. खरे द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, 'मे. के. एल. एंटरप्राइजेस' नामक एक ही ठेकेदार को वाहन मरम्मत के नाम पर करोड़ों रुपये का भुगतान किया गया है। उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, केवल 28 वाहनों की मरम्मत पर ही 3,09,04,905 खर्च किए गए हैं, जबकि अन्य वाहनों का



खर्च जोड़ने पर यह कुल भुगतान 4,17,84,922 से भी अधिक हो जाता है। गाड़ी की असली कीमत से भी ज्यादा आया रिपेयरिंग का बिल! शिकायत में सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह उजागर किया गया है कि कई वाहनों की मरम्मत पर उनकी मूल खरीद कीमत से भी ज्यादा खर्च दिखाया गया है। विशेष रूप से, जिन बोलेरो वाहनों की बाजार कीमत लगभग 9 लाख है, उनकी मरम्मत पर 13 से 16 लाख तक खर्च कर दिए गए। इतना ही नहीं, सबूतों के साथ यह भी आरोप लगाया गया है कि केवल एक बुलेट मोटरसाइकिल की मरम्मत पर पिछले तीन वर्षों में 4,28,862/- (चार लाख अठ्ठावीस हजार आठ सौ बासठ रुपये) की भारी-भरकम राशि खर्च की गई है। शिकायत में उठाए गए प्रमुख सवालः प्रत्येक वाहन की मरम्मत की तकनीकी आवश्यकता को किसने प्रमाणित किया? क्या मरम्मत से पहले और बाद में वाहनों की विधिवत जांच की गई थी? कागजों पर दिखाए गए स्पेयर पार्ट्स क्या वास्तव में वाहनों में बदले गए हैं? ...शेष 7 पर

त्योहारों के बाद अस्पतालों में गहराया रक्त संकट, रतन टिबरेवाला की अपील – हर सोसायटी लगाए एक रक्तदान शिविर!

भाईंदर, (सिटी न्यूज़ मुंबई) त्योहारों और छुट्टियों के बाद मुंबई और उपनगरों के प्रमुख अस्पतालों में रक्त की कमी को देखते हुए समाजसेवी रतन टिबरेवाला ने सामाजिक संस्थाओं, हाउसिंग सोसायटियों और युवा मंडलों से रक्तदान शिविर आयोजित करने की अपील की है। मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए टिबरेवाला ने चिंता जताई कि छुट्टियों के दौरान रक्तदान शिविरों की संख्या कम होने से टाटा मेमोरियल, केईएम, सायन, नायर और जेजे जैसे प्रमुख अस्पतालों में रक्त का स्टॉक काफी कम हो गया है। उन्होंने बताया



कि मुंबई में प्रतिदिन लगभग 1,000 से 1,400 यूनिट रक्त की आवश्यकता होती है। रक्त की कमी से थैलेसीमिया, कैंसर और गंभीर दुर्घटनाओं के मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रक्त की इस कमी को दूर करने के लिए उन्होंने 'एक सोसायटी-एक शिविर' का संकल्प सामने रखा। उन्होंने शहर की प्रत्येक हाउसिंग सोसायटी से अपने परिसर में कम से कम एक रक्तदान शिविर आयोजित करने की अपील की। रतन टिबरेवाला ने बताया कि रक्तदान शिविर आयोजित करने के लिए बड़े आर्थिक खर्च की जरूरत नहीं होती। अधिकृत ब्लड बैंकों की ओर से प्रशिक्षित डॉक्टरों की टीम, मेडिकल स्टाफ और आवश्यक उपकरण निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। आयोजकों को केवल स्थान, बैठने और पेयजल की बुनियादी व्यवस्था करनी होती है। उन्होंने युवाओं से इस अभियान का नेतृत्व करने, स्वयं रक्तदान करने और अन्य लोगों को भी रक्तदान के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में रक्त की कमी किसी एक परिवार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की चिंता का विषय है। ऐसे समय में रक्तदान ही जरूरतमंद मरीजों के लिए जीवनदान साबित हो सकता है।

भिवंडी में ऑनलाइन जुए के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश, 11 आरोपी गिरफ्तार

माणकोली के लोढ़ा परिसर में चल रहा था कथित ऑनलाइन सट्टेबाजी का कारोबार, 32 मोबाइल और 3 लैपटॉप समेत 3.80 लाख का सामान जब्त

सिटी न्यूज़ मुंबई/गनी खान भिवंडीः भिवंडी के नारपोली पुलिस ने ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी के एक नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने माणकोली स्थित लोढ़ा परिसर के एक फ्लैट में छापा मारकर 32 मोबाइल फोन और तीन लैपटॉप जब्त किए हैं। जब्त किए गए सामान की कुल कीमत करीब 3 लाख 80 हजार रुपये बताई गई है। पुलिस के अनुसार, आरोपी कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों और बैंक खातों का इस्तेमाल कर ऑनलाइन जुए का कारोबार चला रहे थे। पुलिस में दर्ज मामले के अनुसार, 16 नवंबर 2026 को सुबह करीब 8 बजे माणकोली स्थित लोढ़ा परिसर के कासा टियारा की डी विंग के फ्लैट नंबर 603 में कार्रवाई की गई। जांच में सामने आया कि आरोपी आपस में मिलीभगत कर अलग-अलग बैंकों के एटीएम कार्ड और मोबाइल सिम कार्ड उपलब्ध कराते थे। इनके माध्यम से पैसों का लेन-देन किया जाता था। पुलिस का आरोप है कि आरोपी फर्जी दस्तावेजों या धोखाधड़ी के जरिए सिम कार्ड हासिल करते थे। इसके बाद सिम कार्ड धारकों ...शेष 7 पर

यह दैनिक मालक-मुद्रक-प्रकाशक, संपादक मोहम्मद शकील अब्दुल रफीक ने सिटी इन्टरप्राजेस धरती कॉम्पलेक्स शॉप नं. 11, एवरशाईन नगर, मिरा रोड (पूर्व), जिल्हा - ठाणे से प्रकाशित किया, मुख्य कार्या लय- धरती कॉम्पलेक्स शॉप नं. 11, एवरशाईन नगर, मिरा रोड (पूर्व), जिल्हा - ठाणे महाराष्ट्र।मुंबई कार्या लय- शॉप नं. 14 उपाध्याय इंडस्ट्रियल इस्टेट, दहिसर चेक नाका, मुंबई इस समाचार पत्र में प्रकाशित सभी समाचारों से संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है किसी भी विवाद का निपटारा मा. ठाणे न्यायालय के अधीन होगा संपादक मो. शकील अ. रफीक : मो. 9869128483
Email : shakeelsahara@gmail.com / citynewsmumbai@gmail.com website : www.citynewsmumbai.in RNI No. : MAHHIN/2012/47486